मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी–अप्रैल, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2001 (फाल्गुन 29, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हुकुमसिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री–

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2000–2001; तथा 16

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 38 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1999–2000, 17

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के अंतर्गत अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के शाहपुरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. वर्ष 2000–2001 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

1 घन्टा

"दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, तथा 95 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सत्रह सौ सोलह करोड़, ग्यारह लाख, इकसठ हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

6. वर्ष 2001-2002 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या-21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या-73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या-91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या-11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या-15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या-62	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
		मांग संख्या-79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.
2 घन्टे	(5)	मांग संख्या-26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-37	पर्यटन
		मांग संख्या-59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या-70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं-पर्यटन
		मांग संख्या-78	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत एवं ग्रामीण विकास
		मांग संख्या-80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति.
2 घन्टे	(6)	मांग संख्या- 3	पुलिस
		मांग संख्या- 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या-65	विमानन विभाग
		मांग संख्या-85	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस.
1 घन्टा	(7)	मांग संख्या-20	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी.
2 घन्टे	(8)	मांग संख्या-22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
		मांग संख्या-53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
		मांग संख्या-81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-87	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-नगरीय प्रशासन एवं विकास.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 मार्च, 2001